उड़ीसा में राज्य बिजली बोर्ड का निर्माण

१४५. **श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार राज्य बिजली बोर्ड का निर्माण अब तक नहीं कर सकी है और यदि ऐसा है, तो इसका कारण क्या है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बोर्ड के निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता चाही थी और यदि चाही थी, तो क्या सहायता चाही थी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†[SETTING UP OF STATE ELECTRICITY BOARD IN ORISSA

145. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Orissa has not so far been able to set up the State Electricity Board and if so, what is the reason therefor; and

(b) whether the State Government sought any help from the Central Government in connection with the setting up of this Board and if so, what was the help sought for and what action has been taken thereon?]

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री ज० ला० हाथी) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य ने अभी तक विद्युत् बोर्ड स्थापित नहीं किया है । इसका मुख्य कारण उपयुक्त व्यक्तियों का न मिलना ही है । इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि बोर्ड के सदस्य के रूप में विधान सभा आदि के सदस्यों, की, उनके विधान सभा की सदस्यता से परित्यक्ति के पश्चात् १२ मास के अन्दर अन्दर, नियुक्ति पर विद्युत् (प्रदाय) नियम, १९४८ द्वारा लगाई गई पाबन्दी को हटा दिया जाये । इससे नियम के कुछ संशोधन करने पड़ेंगे और ये संशोधन अन्य संशोधनों के साथ किये जायगे । देरी से बचाव के लिये, उड़ीसा सरकार ने बोर्ड को १ मार्च, १९६१ को स्थापित करने का निश्चय कर लिया है ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SHRI J. S. L. HATHI): (a) and (b) The Government of Orissa have not yet constituted an Electricity Board for the State, mainly due to shortage of suitable personnel. In view of this difficulty, the State Government had suggested the removal of the restriction imposed by the Electr city (Supply) Act, 1948, on the appointment of members of State Legislature, etc., as members of the Board within a period of 12 months of their resigning the membership of the Legislature. This would involve amendment of the Act and would be taken up along with other amendments. In order to avoid delay, the Government of Orissa have since decided to set up the Board from 1st March, 1961.]

†[ ] English translation.

---

12 NOON

REFERENCE TO THE PROCEDURE FOR PRESENTATION OF THE BUDGET

SHRI BIREN ROY (West Bengal): On a point of information which also brings in the question of privilege, may I ask, Sir, why the Central Budget cannot be presented in a joint session of the two Houses?

MR. CHAIRMAN: It has not been the practice all these years.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): May I point out a new practice that has been started . . .